messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

(I)

"In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 10th June, 1998, agreed without any amendment to the Representation of the People (Amendment) Bill, 1998, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 2nd June, 1998."

(II)

"In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, at its sitting held on the 10th June, 1998, agreed without any amendment to the Merchant Shipping (Amendment) Bill, 1998, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 3rd June, 1998."

THE BUDGET (GENERAL), 1998-99 (Contd.)

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछले दो दिन से....(व्यवधान)

श्री लछमन सिंह: महोदय, पहले मेरी बारी थी?....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आपकी बारी भी आ रही है।....(व्यवधान)

कुमारी सरोज खापर्डे: सर, पहले उनको बोलने दीजिएगा, मैं बाद में बोलूंगी।

उपसभाध्यक्ष: नहीं, आप बोलिए, प्लीज़।....(व्यवधान)

MISS SAROJ KHAPARDE: Let him speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): All this adjustment is being made in deference to the wishes of the House-....(*Interruptions*)... Otherwise, the time is exhausted. I hope everybody will agree with me. ...(*Interruptions*)...

कुमारी सरोज खापर्डे: सर, पिछले दो दिनों से हमारे सदन में बजट पर चर्चा हो रही है और इस सदन में बैठे हुए कई सदस्यों को मुझे सुनने का मौका मिला। कुछ ट्रेज़री बैंचेज़ से, कुछ विरोधी पक्ष से लोग बहुत अच्छा बोले और उन्होंने अपने विचारों को सही ढंग से सदन के सामने रखा। महोदय, मैं इस दिशाहीन, जनविरोधी और मंहगाई बढ़ाने वाला जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने संसद् में पेश किया है उसका विरोध करने हेतु खड़ी हुई हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वदेशी का राग अलापने के साथ स्वदेशी वस्तुओं को उत्पाद शुल्क लगा कर महंगा किया है जिसका परिणाम आम नागरिक को भुगतना पड़ेगा और जिससे आम नागरिक ही प्रभावित हुए हैं। महोदय, आप मुझसे सहमत होंगे, लेकिन आज की स्थिति में आप मुझसे सहमत होंगे या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम, परन्तु जब आप इस तरफ बैठते थे जहां कि हम लोग आज बैठे हैं और हम जब उस तरफ बैठते थे जहां आज आप लोग बैठे हुए हैं, यह सिचुएशन होती तो शायद आप मुझसे सहमत होते, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि एक गरीब आदमी और सिर्फ गरीब आदमी नहीं, हम सभी सुबह उठ कर या दिन भर की थकान भगाने के लिए या मिटाने के लिए एक प्याली चाय ही पीने का प्रयास करते हैं।....(व्यवधान)

डा० महेश चन्द्र शर्मा (राजस्थान): मैं नहीं पीता हूं।...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नहीं, मज़ाक रहने दीजिए, सब पीते हैं।...(व्यवधान)

कुमारी सरोज खापर्डे: हम सभी पीते हैं। आप भी पीते हैं, हम भी पीते हैं। मैंने तो गरीब आदमी का एक उदाहरण दिया....(व्यवधान) ठीक है, आप भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, बहुत अच्छी बात है। परन्तु चाय और दूध पाउडर पर कर लगा कर मंत्री महोदय ने एक प्याली चाय भी हम से दुश्वार कर दी।

महोदय, फिर मैं यहां किसी गरीब आदमी की चर्चा नहीं करूंगी, मुझे हम सभी की चर्चा करनी होगी। महोदय, कभी-कभी हम सामान्य लोगों के बच्चे भी नमकीन का स्वाद लेते थे, परन्तु मंत्रीजी की बड़ी कृपा हुई और उन्होंने उस पर भी कुछ टैक्स लगाया जिस कारण अब नमकीन खाने से भी अपने बच्चे वंचित हो जाएंगे। आज जब थके-मांदे जब हम घर जाते हैं या सुबह-सुबह जब अपने काम पर जाते हैं तो घर की

महिलाएं आप को बहुत बढ़िया नाश्ता बनाकर खिलाती हैं। अब आज आप उन से पूछिए कि क्या हालत है? आज सब्जियों के दाम, दालों के दाम आसमान छू रहे हैं। आप ने मसालों के ऊपर कर लगाकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि हमारी बहनें पकवान बनाते वक्त और मसाले डालते वक्त दो बार सोचेंगी कि कितना मसाला डालना है और उसे कितना स्वादिष्ट बनाना है।

मान्यवर, हमारे गरीब परिवारों की महिलाएं घर की आमदनी बनाए रखने के लिए घर में सिलाई कर के आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न करती रही हैं, परंतु मंत्री महोदय ने सिलाई की मशीनों पर कर लगाकर उन की रोजी-रोटी को छीनने का प्रयास किया है। मान्यवर, एक उम्र के बाद हम सभी को ऐनक की जरूरत जरूर पड़ती है, फिर चाहे वह कम उम्र में लगे या बड़ी उम्र में लगे। हमारे रक्षा मंत्री को कितनी कम उम्र में ऐनक की जरूरत पड़ गयी। आज आप ने ऐनक के लैंसेस और फ्रेम्स के ऊपर भी कर लगा दिया है। क्या इस के लिए हमारे वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र नहीं हैं? मान्यवर, नया सवेरा लानेवाली सरकार की विडंबना तो यह है कि जहां आम उपभोक्ता की वस्तुओं को महंगा बना दिया गया है, वहीं विलासिता की वस्तुएं, जैसे कैलकुलेटर्स, पेजर्स और "सेलफोन" को आप ने काफी सस्ता कर दिया है। मान्यवर, मुझे यह सब देखने के बाद ऐसा महसूस होने लगा है कि वित्त मंत्री जी ने जो बजट संसद के सामने पेश किया है, यह गरीबों का बजट नहीं, है, यह आम लोगों का बजट नहीं है, यह सिर्फ सरमायदारों का है, यह बजट सिर्फ अमीरों का है और अमीरों की सुविधाओं का ही इस बजट में ध्यान रखा गया है। आप ने अपने बजट के जरिए गरीबों को खूब निचोड़ने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी है।

मान्यवर, किसानों के कल्याण का राग आलापने वाली इस सरकार ने किसानों के हितों पर भी बहुत बड़े प्रहार किए हैं। इस सदन में मेरे अन्य साथियों ने भी यूरिया के बारे में चर्चा की हैं और हमारे साथियों ने ही नहीं बल्कि सरकार के सहयोगियों ने भी यूरिया के दाम बढ़ाए जाने से नाराज होकर सरकार की किरकिरी कर डाली है। दूसरी ओर सरकार की इस कार्यवाही से अति-प्रसन्न होकर हमारे उत्तर प्रदेश के किसान नेता श्री टिकैत ने तो प्रधान मंत्री जी के बारे में कहा है कि इस के लिए प्रधान मंत्री जी का सार्वजनिक अभिनंदन हमें करना चाहिए। क्योंकि आपने किसानों की इतनी भलाई की अपना बजट बनाकर। मान्यवर, मुझे समझ में नहीं आता है, यह कैसे विडंबना है कि नैसर्गिक विपदाओं की मार से त्रस्त किसानों के लिए यूरिया की कीमत बढ़ा दी गई है। यह सरकार बाजार में बिक रहे नकली फर्टिलाइजर को रोकने के स्थान पर किसानों की जेबें खाली करने में लगी हुई हैं। इतना ही नहीं, डेरी उत्पादों पर शुल्क लगाया, ट्रेक्टरों पर शुल्क लगाया और ऐसा लगता है कि सरकार ने सारा जो कुछ काम किया है इस बजट के माध्यम से, वह किसान के विरोध में ही किया है। ऐसा संक्षेप में सभी लोगों की नजर आने लगा है।

मान्यवर, कहने को तो आपने कृषि के लिए राशि में 58 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है, परन्तु किसानों को इस राशि से लाभ होने वाला नहीं है। ऐसा साफ नजर आता है क्योंकि प्राकृतिक विपदा कोष में धनराशि का प्रावधान जो है वह दो साल पहले ही कर दिया गया था और उसी के साथ ही उस प्रावधान में राज्यों का हिस्सा भी निर्धारित कर दिया गया था, चाहे प्रदेशों में प्राकृतिक विपदा का प्रकोप कितना ही व्यापक क्यों न हो। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में इस बार प्रकृति ने एक तांडव नृत्य खड़ा कर दिया, लाखों किसानों की फसलें, बागीचे आदि नष्ट हो गए, परन्तु उन्हें राहत नाम की कोई सांत्वना, राहत नाम की कोई तसल्ली न तो केन्द्र सरकार से मिली और न ही राज्य सरकार से मिली है।

मान्यवर, आज सारे देश का जो ध्यान है, यह ध्यान आत्महत्या करने वाले किसानों की ओर गया है, परन्तु इन किसानों का जिनका नुकसान हुआ है नैसर्गिक विपदा के कारण उनके लिए कोई एक निश्चित राशि राहत के रूप में उपलब्ध कराने के स्थान पर हमारे वित्त मंत्री जी क्रेडिट कार्ड देकर गरीब किसान का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं रहे हैं। इसका उल्लेख मैं विरोधी पक्ष में बैठी हूं इसलिए नहीं कर रही हूं, आपकी पार्टी के ही जो हमारे नायडू साहब हैं, उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया है कि आप किस तरह से किसानों की खिल्ली उड़ाते हैं, किसानों का किस तरह से आप मजाक उड़ाते हैं। क्रेडिट कार्ड देना आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड तो वह तभी इस्तेमाल कर सकेगा, जब अपने खाते में वह पैसा डाल सकेगा।

मान्यवर, मुझे लगता है कि सरकार ने अपने बजट में सारे देश में फसल का बीमा लागू करने की कहीं पर बात नहीं की है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगी कि सारे देश में, और विशेषकर महाराष्ट्र में फसल बीमा लागू करे, जिसमें छोटे और मध्यम वर्ग के जो किसान हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो किसान हैं, उन किसानों का जो प्रीमियम हो, उस प्रीमियम को सरकार स्वयं वहन करे।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान बजट में जो स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने प्रावधान किया है, उसकी ओर दिलाना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले मैं जरा कुछ कहना चाहूंगी। अभी दोपहर में मैं, प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा जी द्वारा इस सदन में दिया हुआ जो भाषण था, उस भाषण को मैं पढ़ रही थी। उस भाषण को पढ़ते-पढ़ते मैंने देखा, जो मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगी।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा कि:—

> "यह दुर्भाग्य रहा इस देश का कि एमरजेंसी के वक्त के दौरान उठाए गए कुछ कदमों से जनसंख्या नियंत्रण की बात लोगों के दिमाग से निकल गई। फैमिली-प्लानिंग करनी चाहिए, जनंख्या को कम करना चाहिए, इसके खिलाफ एक वातावरण बन गया जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश की जनसंख्या आज बढ़ती जा रही है।"

महोदय, मैं विनम्रता से कहना चाहूंगी कि एमरजेंसी के जमाने में हुई ज्यादतियों का समर्थन करने के लिए मैं यहां खड़ी नहीं हुई हूं, परन्तु उस वक्त उस सरकार का निश्चित रूप से यह उद्देश्य था कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना चाहिए। उस वक्त सरकार की ओर से जो नीतियां अपनाई गई थीं। वे देश के हित में थीं। उनका उस समय अगर दुष्प्रचार न किया जाता तो हमारे देश की जनसंख्या में आज काफी हद तक नियंत्रण हमें दिखाई देता। मान्यवर, स्वास्थ्य के बारे में बोलते हुए मुझे यह कहना पड़ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की अपनी समस्याएं होती हैं। सामाजिक और लोक-लाज के कारण वह अपनी हर बीमारी को बता नहीं सकती और गांव के एक छोटे से कमरे के स्वास्थ्य केन्द्र में, जहां केवल एक पुरूष डाक्टर होता है और वह पुरुष डाक्टर अनेक युवा मर्दों के साथ, महिलाओं के साथ, वृद्धों के साथ काफी व्यस्त रहता है, ऐसी हालत में वह महिला उसके पास जाकर उसको अपना रोग नहीं बता सकती है वह सिर्फ इतना कहती है कि तबीयत ठीक नहीं है और दवा लेकर आ जाती है और यह समझती है कि शायद मेरी तकदीर में यही था कि मुझे दर्द निवारक दवा लेकर अपने आपको ठीक करना था। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि मैं अपेक्षा करती थी कि इस बजट में गांवों में एक योग्य महिला डाक्टर की विज़िट का प्रावधान करने की बात कही जाएगी। इस बजट में जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक दवाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए था और इसी प्रकार जैसा मैंने अभी जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कहा, इस बजट में जनसंख्या नियंत्रण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए था, परन्तु सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। परिवार कल्याण की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई है और मैं समझती हूं कि इसकी इतनी अनदेखी करना सरकार के लिए ठीक नहीं है।

मान्यवर, सरकार ने आवास निर्माण के बारे में भी बड़े लम्बे-चौड़े वायदे किए हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आवास निर्माण के बारे में किए गए लम्बे-चौड़े वायदों को मूर्त रूप कैसे दिया जाएगा और इसका बजट में कोई उल्लेख भी नहीं किया गया है। फिर मकान अगर बन भी जाते हैं तो वे आम गरीब इंसान को कैसे उपलब्ध होंगे, इसका कोई जिक्र हमारे बजट में नहीं है। उन मकानों में बिजली, पानी सीवरेज जैसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये उपलब्ध होंगी या नहीं, इसका भी उल्लेख नहीं है। इसके साथ-साथ पटरी पर सोने वाले लोगों के लिए सरकार की क्या योजना है, इसकी भी जानकारी इस सदन को दी जानी चाहिए थी, लेकिन इसका भी बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, शिक्षा के लिए आपने 4,245 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरी समझ से यह समस्त देश के लिए काफी नहीं है। इसका सबसे अधिक असर अगर किसी पर होगा तो वह होगा समाज के कमजोर वर्गों पर, दलितों पर क्योंकि उनके लिए अलग से व्यवस्था कर पाना सरकार के लिए संभव नहीं हो पाएगा जबकि इस वर्ग में शिक्षा का प्रसार करने की ज्यादा आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं और एक मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। यह जो बजट पेश किया गया है संसद में, यह बजट बेकारी की समस्या का निदान करने हेतु वचनबद्ध नहीं है। इतना ही नहीं, सरकारी सेवाएं भी उपलब्ध नहीं करा सकता है। उद्योग का विकास न होने के कारण इम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा है और गांवों में नैसर्गिक विपत्तियों के कारण काम भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस बजट से ऐसा नहीं लगता है कि इस देश की बेकारी कम हो पाएगी। इन सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद, इस बजट को ठीक ढंग से देखने के बाद, पढ़ने के बाद मैं वाकयी इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि इस जनविरोधी बजट के बारे में मुझे समर्थन करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने जरूर समर्थन किया होता अगर इसमें थोड़ी सी भी गुंजाइश होती। वैसे भी विरोधी पक्ष के नाते हम लोग यहां विरोध

करने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए समर्थन करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मैंने जो मुद्दे उठाए, इन मुद्दों का आपने जरा भी ध्यान रखा होता तो मैंने कहा होता कि आपका जो बजट है, वह काफी अच्छा है। जिन मुद्दों को मैंने आपके सामने रखा है, उन मुद्दों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे आपके बजट का विरोध करना चाहिए। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं। आपने मुझे जो मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Dr. Arun Kumar Sarma. It is his maiden speech.

DR. ARUN KUMAR SARMA (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, this is my maiden speech in this House. We have already deliberated on this subject in detail and I have been listening to most of the speakers of this august House. I must say that I am not an economist. I was teaching in a University, an Agriculture University of Assam before coming to this Parliament. Whatever has been deliberated in this House, it tempted me to think about it from a different angle. For the last 50 years we have been deliberating on the budgets, on the Indian budgets prepared by the Finance Ministry. Every time we just try to find out loopholes in the Indian Budget prepared by the Finance Ministry without going into real crux of the problems of this country. The point I want to make is, that we do not have adequate resources to meet the budgetary requirements.

After we became independent, we inherited a variety of systems, a machinery from the British regime. The British regime tried to explore and exploit resources from the States and the provinces at that time. The usual practice of British was to bring money from the States and provinces, accumulate it at New Delhi and then take it away to the United Kingdom for welfare activities there. After this was brought to our own administrative set-up, we could not make much change in the administrative system and the planning process. And that is why we could do anything, but just blame the machinery through which the Budget is prepared. We do not have the resources. For the last 50 years, the planning process has been so defective that we could not do anything to increase the production level, to have the minimum infrastructure so as to continue production for generation of resources.

We thought of becoming a welfare State. We floated lot of *Yojanas*. We did lot of planning. We prepared lot of schemes, a lot of projects. They become rather a liability for the country, instead of resulting in productive assets. That is where the Planning Commission failed.

What was the prescribed role of the Planning Commission? To lay down the priorities and finalise the schemes to be taken up in different parts of the country, on the basis of the proposals from the State Governments. But what was done? The entire planning process was medulated at the behest of the ruling party at the Centre and the Union Cabinet. Though it was called the Planning Commission, in effect, it was just an administrative body, a subordinate body, of the Union Cabinet. Funds were distributed at the whims of some Ministers; may be the Prime Minister, the Finance Minister, or, some other Minister. Threrfore, equitable distribution to the appropriate sectors did not take place.

I can give one example here. I belong to the North-East. We have thirty-three per cent of the water resources in the country. Because of the steep hills in this region, we could have more dams for production of cheap hydro power. The North-Eastern Region has the potential of producing 55,000 MW of hydro power. But I am sorry to say, till today, our region, the North-Eastern Region, remains a power-deficient area.

Today, Sir, the country is suffering because of shortage of power. Power is the basic infrastructure for development.

But we have not tapped this potential in the North-Eastern Region.

Sir, we have borrowed a lot of money from foreign countries. We have become indebted, to a great extent. We did not have resources. We borrowed. What did we do? We created jobs in the public sector, in the Government sector, capable of producing nothing. We retained the education system of the British. What is the result? Lakhs and lakhs of graduates, educated youth, are coming out every year, capable of applying for Governmnt jobs only. They are not capable of earning their own livelihood with the kind of education they have. I do not blame our youth. We have just inherited this system from the British, which was meant for the creation of a certain number of bureaucrats, a certain number of clerks. The country could not adopt any effective plan programme.

What is the position in which we find ourselves today as a result of this? One hon. Member Shri Pranab Mukherjee pointed out in his speach today. It touched my heart. He said that the loan burden — both principal and interest — is more than our revenue receipts, i.e. whatever amount we are earning from within our country an amount greater than that is being paid in the form of loan repayment. It means, we are in the stage of bankruptcy. Who is to be blamed now?

From my student days, I have been seeing a lot of debate taking place in both Houses of Parliament and in the State Legislatures. I find that it is mostly to blame the other politicians and point out as to what wrongs they did. I do not know what kind of constructive deliberations we have made to really find out the truth. That is the crux of the problem. This is what we have to do. This is the need of the hour. I hope, in future, we will address ourselves to this.

I strongly feel — this may not be acceptable to most of the learned Members, but, as a new Member, I must express my viewpoint — that we must change our Constitution. There should be another Constituent Assembly. Let us find out as to what are the problems, what are the real problems of the country and the practical solutions to these. If the real problems of the remote corners of the country are properly dealt with, we need not invest much in security, we need not invest much in defence. Nearly 40 per cent of our Budget goes for defence and internal security.

The situation in Assam and in most of the other States in the North-East is such that the State Government are not capable of paying the salary of their own employees, not to speak of taking up any developmental activity. What is the reason? After the Independence, the Constitution was amended time and again to curtail the power of the State Governments to raise their own resources. Amending the Seventh Schedule, some of the items were transferred from the State List to the Concurrent List and from the Concurrent List to the Union List. Now the Central Government is blaming all the State Governments that they are not capable of delivering goods to the people. All the liabilities were left with the State Governments and the resource-earning items came to the Union Government. The Centre enjoy 80 per cent of the total resources, leaving the States with the liabilities only.

In India, the first oil refinery and the first tea garden was established in Assam. Coalmines were established a railway line was installed and so many other developmental activities were taking place in Assam during the British time.

But what is the fate of Assam now? Why has the insurgency cropped? Without solving their real problem, only blaming the people of Assam or the people of the North-East will not solve the problem neither in Assam nor in any other State of the country. Hon. Member, Mr. Naidu, says that the regional imbalance is very much because, at the behest

of some influential politicians of the ruling party, the Planning Commission decides what Plan fund will go to which part. That is the reason why, despite having all the water resources, we do not have important power projects to generate adequate power which is the immediate infrastructure needed for any development activity. Even for education of children, we need power. Power is the basic need for any developemnt, but we could not generate it sufficiently for the last 50 years. This is shame for our country which is having so much of population, so many educated people and so many strong personalities. The time has come to review the entire system.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I must emphasise one issue of the Planning Commission. Whatever the Planning Commission has practised during the last 50 years through different planning processes, it resulted reasonal imbalances in development therefore it should be a constitutional body. There should be definite criteria on what kind of fund disbursement and planning process will be taken up by the Planning Commission. The Finance Commission is a constitutional body. So, definite guidelines are followed by it. But most of the funds allocated through the Planning Commission during the period have gone to the developed States. There are many Central Sector schemes, in duplication with the State schemes. Education, health etc. were State subjects. They have been transferred to the Concurrent List. Now there is duplication in most of the items. For education, there is the Union Budget and there are also the State Budgets. For agriculture also there are the State Budgets and there is the Union Budget. There is unnecessary duplication in most of the subjects.

If you take one scheme the method of the scheme is such that by the time it reaches remote areas of the North-East, another scheme starts. The privilege goes to the developed States because they can get the full benefit of the scheme. They are privileged to know the details of the scheme at the beginning and they have sufficient funds to give the matching grant. No State Government in the North-East is in a position to give the matching grant. So, whatever money is given in the name of Central Planning, it does not really reach the common people of the North-East. It is not the case of only the North-East, but it is also the case of Bihar and some other parts of the country. so, there should be a drastic change in the entire administrative set-up and we must have a review.

We must have a review of the work in the public sector, in all the Government and even the State Government offices. A number of surplus employees are having no work. Some may, of course, be required at a particular time, but not always. We are just paying them for nothing. There is no production. Because we inherited a socilaistic system and have become a welfare State, we can not afford to retrench them.

Sir, we could not adopt advance technology in the North-East in spite of a large sum of money allocated to the North-Eastern States. We did not import proper technology. Therefore, it is said that the money has gone to wrong places. Some of the money went into the hands of the extremists as well. Therefore, the Centre is reluctant to give monetary assistance to the North-Eastern States. When India was attacked by China in 1962—I was a very small child then—I remember a message went around of the then Prime Minister who said, "My Heart goes out with the people of Assam". Since the people of Assam could not be protected and the Indian Army also fled, the bureaucracy and the Planning Commission developed the impression—the politicians at that time also felt—that it was useless to invest in the North-East, because they felt that any moment this area might go to China. This has been reflected in the recent statement made by our Defence Minister, when he visited the North East. That is the reason why there was no proper investment in the North-East. Even in spite of the commit-

ments of both the then Prime Ministers, Shri H.D. Deve Gowda and Shri Gujral and also of the present Prime Minister, when he visited the North East, very little has been reflected in the present Budget. That is why we feel that something tangent needs to be done to meet the basic needs of the North-Eastern States. India basically being an agricultural country, greater emphasis has to be given to agriculture. I must congratulate the former Finance Minister, Dr. Manmohan Singh, who was the first person to take a bold step in stopping the practice of spoon feeding. Earlier most of the population was being spoon-fed by borrowing from foreign countries. He attempted to correct the mismanagement of the entire financial system of the country. Nodoubt, it has also produced some bad results. Our industries, even the smaller industries in the consumer goods sectors have to compete with the foreign industries in the field of potato-chips etc. Of course, we must have competition and we should not always be dependent on foreign loans. We must generate goods and services on our own. We must be self-dependent. That was the starting point when Dr. Manmohan Singh started financial reforms. I feel a special debate on this subject should be held so that for the future we can carve out our own pattern of resource generation for making our basic infrastructure.

Sir, the economy of the North-East depends on animal husbandry, agriculture, pisciculture, handloom and textile industries. The situation is such that a lot of agriculture and horticulture items get rotten, because there is no transportation system, because there is no fruit and vegetable preservation system. For agricultural processes also our farmers have to invest. Here, one has to spend more to get a remunerative price.

They have to face more trouble. They have to spend more for selling their produce and to get a remunerative price because of lack of communication facilities and storage facilities. The weather condition is very unfavouable most of the time because of the geopgraphical situation. The minimum infrastructure needed for that area is not there. The minimum development of the road communication is not there. The Central Government is planning to construct express highways to link metroplitan cities with some parts of the country. But for the North-East this is never done. The North-East is still linked to the rest of India by only a 32 KM stretch of land. A single track railway line and a narrow highway servey as the only link with the main land. Ninety per cent of the North East has borders with the neighbouring countries. On the peripheries it has links with some neighbouring countries. If a farmer or if a trader or if an industrialist wants to have trade with people in Mumbai or Delhi or Chennai or Calcutta, it becomes uneconomical because the distance is too far. They should be allowed to have trade with the localities in the neighbouring countries. But after our Independence that was stopped. The foreign tourists were not allowed to go to the North-East. Presently there are five States which have been restricted to foreign tourists for visiting purpose. Tourism is another aspect where the North-East can be developed. But for this purpose the minimum infrastructure was not provided. The basic infrastructure for sustainable development of the areas was not provided even after 50 years of our independence. Now, we are going in for global competition. But the people of the North-East are not in a position to compete even with some of the developed States of the country. We are just trying to have foreign investment. When our domestic investors are not willing to come to the North-East and invest, how can foreign investors come to the North-East and invest? These are imaginable things We must be practicable so that every part of the country can develop equally. Whatever discrimination is there, it should be removed. Based on the resources the States have, there should be equitable distribution of funds.

The Central Government should not be the master of all the subjects. The Central Government should keep with itself some important subjects like currency, defence, communication, security and external affairs. The ramaining subjects should be given to the States. Now, what is the grievance of the common people in the remote areas? They say that the Central Government is exploiting them and not giving them money. Is it a real thing? They should be given their legitimate due to develop themselves. The Central Government should be able to say, "This is part of your share money. There is no need to blame anybody. You develop yourself." Then, there will be competition. Then, every state will think, "This is our share money. We cannot get more than that." Now, everybody is coming to the Central Government with a begging bowl. Everybody tries to influence the Planning commission and the Ministers to get more money. whoever can influence them will get the money. What about the inaccessable States which are far away which could not come on par with any of the developed States of the country, after the British period? We feel that there should be a drastic change in the entire planning system and the budget making system and the financial management of the country. For that, I hope and pray that another Constituent Assembly should be constituted. Let us discuss the matter threadbare and find out what really can lead our country to become stronger and developed to compete with the other developed countries of the world.

With these words I conclude my maiden speech. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Dr. Sarma, thank you. I would like to assure you that the entire North-East has a very important place in the heart of India. There might have been some inadequacies at any given point of time. All the Governments at the Centre have cherished the people of Assam as very valuable colleagues and feel proud of the State's resorces. We do not have any kind of discrimination against North-East. They should not feel alienated.

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, तीन दिन की अनवरत प्रतीक्षा के बाद आपकी कृपा से अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैं इस किसानोन्मुखी, ग्रामोन्मुखी और रोजगार-परक जनोन्मुखी और लोकप्रिय बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

महोदय, 11 व 13 मई को परमाणु परिक्षणों के उपरांत जिस प्रकार से विश्व के सम्पन्न राष्ट्रों, यथा अमेरिका, जर्मनी, जापान और आस्ट्रेलिया जैसे देशों ने हमारे देश के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणाएं की और यही नहीं बल्कि विश्व बैंक के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से हमारे देश की आर्थिक घेराबंदी करने की कोशिश की, उस परिप्रेक्ष्य में, उस पृष्ठभूमि में इस सरकार के माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह एक सराहनीय प्रयास है और मैं समझता हूं कि इसकी प्रशंसा करनी ही चाहिये। महोदय, जब कि सम्पूर्ण राष्ट्रवासी इन विदेशी प्रतिबंधों के कारण काफी कठोर बजट की कल्पना कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे, वैसी स्थिति में वर्तमान बजट ऐसा लगता है जैसे गर्मी के उपरान्त मानसून की पहली बरसात हो। इस तरह का सुखद अभास और चिंता मुक्त करने वाला यह बजट सिद्ध हुआ है। महोदय, मैंने यहां पिछले तीन दिनों में प्रतिपक्ष के नेता द्वारा और ट्रेजरी बैंच के नेताओं द्वारा बजट के संबंध में प्रकट की गई प्रतिक्रियाओं को सुना है। माननीय नेता प्रतिपक्ष और यहां बैठे हुये आदरणीय प्रणव मुखर्जी और अभी अभी जो यहां से तशरीफ ले गये हैं, पूर्व योजना मंत्री मान्यवर अलघ जी, श्री वेंकैया नायडू और आदरणीय श्री शर्मा जी द्वारा बजट की जो रचनात्मक आलोचना हई है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने बजट में जो अच्छाइयां है उनको उजागर किया है और उसमें जो खामियां हैं उनको बताया है लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर इस बजट की आलोचना करने के नाम पर आलोचना की है। कुछ लोगों ने इसे जन-विरोधी बताया है, कुछ लोगों ने इसे दिशा-हीन बताया है और कुछ लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डिफरेंट वाइस में बोलते हैं, विभिन्न भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। मान्यवर, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। हमारे देश के

एक बहुत बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री इन्द्र कुमार गुजराल और युनाइटेड फ्रंट के एक दूसरे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उसको मैं यहां उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय श्री गुजराल जी ने कहा है कि रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी नहीं करनी चाहिये। उसमें कुछ कटौती करके उस धन को सामाजिक विकास की योजनाओं पर खर्च करना चाहिये और वहीं माननीय मुलायम सिंह ने कहा है कि रक्षा बजट में और वृद्धि करनी चाहिये थी। यह बातें विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं जो कि विभिन्न भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट वाइस में बोलते हैं। युनाइटेड फ्रंट के दो बड़े नेता बिल्कुल विपरीत बात कहते है और हमारे ऊपर इस तरह का झूठा आरोप लगाते हैं। मान्यवर, बजट कैसा भी हो, आलोचना करने वाले आलोचना करते ही हैं। मैं यह कह सकता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, जिसे हम कह सकते हैं कि सरल बजट है, रोजगारोन्मुख बजट है, किसानोन्मुख बजट है और इम्पलायमेंट का सृजन करने वाला बजट है। उसकी तारीफ करनी चाहिये। मैं इसलिये भी तारीफ करना चाहता हूं क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के सामाजिक विकास की धुरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर, उसकी स्थिति पर और उसकी गतिशीलता पर बहुत कुछ निर्भर करती है।

मान्यवर, कृषि के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से निरंतर गिरावट आ रही थी। कृषि के क्षेत्र में हम केवल एक या दो वर्ष के लिये आत्म-निर्भर हो कर पुनः दुसरों पर निर्भर हो गए। इस देश में रहने वाले प्रति व्यक्ति के लिये खाद्यान्न की उपलब्धता निरंतर कम हो रही है। एक कृषि प्रधान देश के लिये यह शर्म की बात है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कृषि को बढ़ावा देने के लिये कृषि बजट में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है। यही नहीं, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 1233 करोड़ रुपए की वृद्धि कर के 8182 करोड़ रुपए कर दिया है। सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 268 करोड़ रुपया बढ़ाया गया है। इंदिरा आवास योजना के माध्यम से जो पिछले वर्ष 1144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, इस वर्ष 1600 करोड़ रुपए का प्रवधान किया गया है। यूरिया खाद पर यद्यपि एक रुपये किलो के हिसाब से माननीय वित्त मंत्री जी ने वृद्धि करने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जन भावनाओं को ध्यान में रख कर उन्होंने इसे घटा कर 50 प्रतिशत कर दिया और मैं समझता हूं कि हम सब की भावनाओं का आदर करते हुये शायद वित्त मंत्री इस वृद्धि को भी वापिस ले लेंगे। ग्रामीण बैंकों के लिये माननीय वित्त मंत्री ने 250 करोड़ रुपए अधिक का आबंटन किया है। नाबार्ड की हिस्सा पूंजी में वृद्धि करने के लिये 500 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। ग्रामीण जलापूर्ति के लिये 1627 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एकीकृत सिंचाई योजनाओं के लिये 58 प्रतिशत आबंटन में वृद्धि की गई है और प्रयोग के तौर पर भारत के 24 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नवीन फसल बीमा योजना प्रारम्भ करने की बात की है। पेयजल की सुविधा, खाद, बीज, कीटानाशक आदि चीजों की आसान खरीद के लिये किसान क्रेडिट कार्ड की बात कही है। यद्यपि इसमें **यह है कि इसको किस तरह से कार्यान्वित किया जाएगा लेकिन मैं समझता हूं कि सब के साथ बैठ कर के कोई न कोई योजना ठीक से बनेगी। यदि किसान क्रेडिट कार्ड उचित योजना बना कर के किसानों को ठीक से उपलब्ध करवा दिया गया तो गांवों में रहने वाले किसानों की स्थिति में भारी परिवर्तन होगा। मैं समझता हूं कि इस देश में रहने वाले लोग जो विशेष रूप से ग्रामीण जनता है, गांवों में रहने वाले लोग हैं, जिनकी आबादी लगभग 65-66 करोड़ होगी, उनकी आर्थिक-स्थिति में आशातीत सुधार होगा। यदि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा क्योंकि इस देश की आर्थिक स्थिति गांवों में रहने वालों की आर्थिक सिथति पर निर्भर करती है। एक ऐसी स्थिति का निर्माण हो सकता है जहां आज हम विदेशों से खाद्यान्न आयात करने के लिए मजबूर हैं, इस योजना के सफलतापूर्वक लागू होने के बाद हम न केवल आत्म-निर्भर होंगे बल्कि विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात कर सकेंगे। परन्तु, मैं एक बात वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं। जो यह घोषणा की गई थी कि हम ग्रामीण विकास और कृषि के क्षेत्र में अपने सकल घरेलू उत्पाद का 60 प्रतिशत इनवेस्ट करेंगे, अभी उस लक्ष्य से हम दूर है लेकिन हमारा विश्वास है कि क्रमशः हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, आने वाले दिनों में शायद हम अपने बजट का 60 प्रतिशत कृषि की अर्थ-व्यवस्था पर खर्च कर पाएंगे।**

मैं इसलिए भी प्रशंसा करना चाहता हूं इस बजट की कि शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्र में जिसकी निरंतर उपेक्षा की गयी है इसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने 50 परसेंट की वृद्धि की है और पिछले वर्ष की तुलना में जहां पिछले वर्ष 4,715.85 करोड़ का आवंटन किया गया था इस वर्ष 7,047.12 करोड़ का आवंटन इस मद में किया गया है। यह राशि अभी भी 6 परसेंट जी०डी०पी०—से काफी कम है। लेकिन जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि यह जो हमारी वर्तमान योजना अवधि है, जो

हमारी नवीं योजना है इसके अंत तक शायद 6 परसेंट का जो हमारा लक्ष्य है उसे हम प्राप्त कर लेंगे।

युवा और खेल-कूद के लिए यद्यपि 158.32 करोड़ से वृद्धि करके 214.76 करोड़ कर दिए गए है परंतु भारत जैसे विशाल देश के लिए मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह राशि अभी भी अपर्याप्त है। पिछले दिनों में ओलम्पिक और एशियाड में जो हमारा डिसमल परफारमेंस रहा है जिसे देखकर कहा जा सकता है कि हमारे देश का गौरव इससे बहुत घटा है, जहां 1952 में एशियाई खेलों में भारत प्रथम नम्बर पर था वहां आज हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है, इस सारी स्थिति को देखते हुए इस क्षेत्र में और अधिक विनिवेश करने की योजना होनी चाहिए। यद्यपि वृद्धि की गयी है लेकिन यह अपर्याप्त है भारत जैसे विशाल देश को देखते हुए।

शिक्षा के क्षेत्र में आपरेशन ब्लैक बोर्ड के मद में केवल 3 करोड़ की वृद्धि की गयी है। मान्यवर, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का जो इस देश का लक्ष्य है जो हमारा कांस्टीटयूशनल आब्लीगेशन है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यह राशि बहुत कम है और इस मद में राशि को बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

मान्यवर, कंप्यूटर शिक्षा के लिए भी आवंटन बहुत कम किया गया है। पिछले वर्ष इस मद में 20 करोड़ का आवंटन किया गया था लेकिन इस वर्ष पता नहीं किस कारण से 10 करोड़ की राशि घटा करके केवल 10 करोड़ इसमें किया गया है जबकि कुछ लोगों का अपना आंकलन है कि आने वाले दिनों में जिन्हें कंप्यूटर की शिक्षा नहीं मालूम होगी, जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होगा वे निरक्षर के समान होंगे। कंप्यूटर के ज्ञान की बड़ी आवश्यकता आज हर क्षेत्र में है। इसे देखते हुए कंप्यूटर शिक्षा पर और अधिक आवंटन करने की आवश्यकता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि इस पर अवश्य ध्यान दें।

मान्यवर, प्रोद्योगिकी संस्थानों, हमारे जो आई०आई०टीज० हैं पिछले दिनों इनकी स्थिति में बड़ी गिरावट आई है। ये हमारे देश के प्रेस्टिजियस इंस्टीटयूट्स हैं और इनके माध्यम से हमारे देश में काफी विकास हुआ है। लेकिन कम विनिवेश की वजह से इन प्रोद्योगिकी संस्थानों की दशा निरंतर खराब हुई है। यह स्वागत योग्य बात है कि इस साल माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष के 224.51 करोड़ के विपरीत 310.76 करोड़ रुपया रखा है। मेरा विश्वास है कि इस आवंटन से इन संस्थानों की स्थिति कुछ न कुछ ठीक हो सकेगी।

मान्यवर, इस बजट में सर्वाधिक जो खलने वाली बात है वह है व्यवसायिक शिक्षा की उपेक्षा । वोकेशनल एजूकेशन के बारे में हमारे सभी दलों के सभी नेतागण समय समय पर अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। लेकिन इस वर्ष व्यवसायिक शिक्षा के मद में पिछले साल जहां संशोधित बजट में 20 करोड़ था उसके विपरीत इस वर्ष केवल 10 करोड़ रखे गए है। मैं चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी से कि इस पर अवश्य ध्यान दें। इससे देश की बेरोजगारी दूर हो सकती है।

मान्यवर, मैं इस अवसर पर माननीय वित्त मंत्री जी और इस माननीय सदन के माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान इस देश के विश्वविद्यालय के शिक्षकों और डिग्री कालेज के शिक्षकों की इस मांग की ओर दिलाना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो संस्तुत वेतनमान देने की बात की है जो रिकमेंडेशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पड़ा हुआ है (माननीय मंत्री जी के विचारार्थ) इस पर ध्यान दिया जाए। उन्हें स्वीकार किया जाए जिससे कि इंस्टीटयूशंस में, विश्वविद्यालयों में, डिग्री कालेजों में, शैक्षणिक वातावरण में सुधार हो और विद्यार्थियों को ठीक से शिक्षा प्राप्त हो सके।

मान्यवर, रक्षा के बजट में 14.13 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, उनका जो रक्षा बजट है, उनकी तुलना में हमारा रक्षा बजट बहुत ही कम है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो चुनौतियां हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इसमें और अधिक प्रावधान करना चाहिए। वैसे यह खुशी की बात है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आवश्यकतानुसार इस मद में और आवंटन किया जा सकता है। मैं इस बजट का स्वागत करना चाहूंगा क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस समय हमारे सामने जो विश्वव्यापी चुनौतियां हैं उसे देखते हुए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 2608 करोड़ का आवंटन किया है जो कि पिछले वर्ष से 60 प्रसेंट के लगभग बढ़ा दिया है। इसी प्रकार से अंतरिक्ष विभाग के लिए 52 परसेंट की वृद्धि की है। यह स्वागत योग्य कदम है और चुनौती को देखते हुए यह आवश्यक भी था।

महोदय, मैं एक बात आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आय कर देने वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए कहना चाहता हूं। यद्यपि माननीय वित्त मंत्री जी ने आयकर की सीमा 40 हजार से बढ़ा करके 50 हजार कर दी है, परन्तु 60000 से ले करके डेढ़ लाख रुपये तक जिन लोगों की कुल आय है उनके लिए आय कर की दर 20 फीसदी है और डेढ़ लाख रुपये से ऊपर

आय वाले सभी लोगों की चाहे उनकी आय चार लाख, पांच लाख कुछ भी हो उनके लिए आयकर की दर 30 प्रतिशत है। मैं चाहता हूं और मैं नहीं, मैं समझता हूं कि इस देश के सभी नौकरी पेशा लोग चाहते हैं जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं समाचार-पत्रों के माध्यम से व्यक्त हुई हैं इन दोनों के बीच में 20 फीसदी और 30 फीसदी के बीच में आयकर की एक दर और इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। डेढ़ लाख जिनकी आय है उससे ज्यादा और ढाई लाख जिनकी आय है उससे कम के लिए 25 प्रतिशत की आयकर की दर एक और उसमें इंट्रोड्यूस की जा सकती है। इससे मैं समझता हूं कि आय करदाताओं को थोड़ा फायदा होगा और इससे वित्त मंत्री जी का कुछ विशेष नुकसान नहीं होगा।

मान्यवर, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने स्वदेशी को विश्व अर्थ व्यवस्था से जोड़ने का एक अच्छा प्रयास किया है। मंदी के दौर से गुजर रही इस अर्थ व्यवस्था में जान फूंकने का प्रयास किया गया है। घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए यद्यपि कुछ संरक्षणवाद का सहारा लिया गया है, परन्तु इसमें एक ओर जहां भारतीय अर्थ व्यवस्था विदेशी पूंजी पर पूरी तरह से आश्रित नहीं रहेगी, कुछ स्वावलंबन की भावना बढ़ेगी वहीं पर विदेशी पूंजी को भी आकृष्ट करने की पूरी कोशिश की गई है। विदेशी पूंजी का भी प्रभाव बना रहेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में और संचार जैसे जो आधारभूत क्षेत्र हैं उनमें भी योजनागत व्यय में 35 फीसदी वृद्धि की गई है। इससे पूंजी बाजार में हलचल तेज होगी और साथ ही औद्योगिक गतिविधियों में चौतरफा तेजी आयेगी। मान्यवर, बीमा के क्षेत्र में जो निजी स्वदेशी कंपनियों को खोल दिया गया है उससे वित्तीय क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा होगी। मैं समझता हूं कि इससे हमारे देश में और अधिक बचत होगी जिससे कि इस देश की इंडस्ट्री को फायदा होगा।

मैं वित्त मंत्री जी के इस साहसिक कदम की प्रशंसा करता हूं और इसलिए इस बजट का समर्थन करता हूं।

इन शब्दों के साथ, पुनः आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

SHRI LACHMAN SINGH (Haryana): Mr. Vice-Chairman, sir, many hon. Members have talked about certain things which are there in the Budget. It is customary that when we are in the Government, we support the Budget. But when we are in the Opposition, we oppose it. I will not adopt this method. There are very good things in the Budget. I would like to support those things. For example, take the case of housing. It is a very good thing. The present Finance Minister has adopted a liberal attitude. There would be no wealth tax for five years. It would be 100 per cent free for the first five years and 30 per cent for another five years. But I would like to request the Finance Minister to add one thing into it. The Rent Control Act should also be amended so that the owner can be in a position to eject the tenant after five years or after ten years; let it be ten years. I don't mind. But there should not be perpetual ownership of the tenant. Then I am sure that thousands of people will get employment and particularly people of Bihar and U.P. will be benefited because thousands of buildings, commercial as well as residential, will be built in a very short time. Secondly, I would like to say that when I was the Industry Minister in Haryana, people used to see me in Delhi regarding subsidies. Mr. George, who is a very intelligent man has changed his views now; he has become a rightist, he is sitting in front of me. So he will appreciate that the subsidies have destroyed our country. So some subsidies must be abolished. Take the case of gas and petrol pumps. One of the Ministers was fined Rs.50 lakhs by the Supreme Court on allocation of petrol pumps. So, the Vajpayee Government consisting of 18 parties should immediately abolish this system and this should be free. Anybody who wants to install a petrol pump or a gas agency can do it in no time. Then, let the market prevail and the rate prevalent in the market will be available to everybody. Why should the Government cling to that and sit on that by saying that they will allot Petrol Pump and gas Agency. Sir, I can take an oath and say that even now lakhs of rupees are given for getting allotment even in these Committees. That is a hard fact; so it should be abolished. Why does the Government want to keep it with them? Let it be free. Everything should be free. Dr. Manmohan Singh has paved the way

and Mr. Chidambaram followed it. Same is the policy of Mr. Sinha at the moment. There may be some little changes; I do not think there are a lot of changes. So I request the Finance Minister to decide it in the Cabinet meeting. Secondly, women Reservation Bill should come in the present session so that the reserved constituencies can also be changed. There is heart-burning in the people when they see that some constituencies are reserved for the last 40-50 years. Ambala is reserved for the last 40 years and same is the case with Sirsa. So this is not fair. It should be changed and Govt. will get 2/3rds majority for Amendment of Constitution. The entire House says that you bring the Bill and it will be passed. Sir, one thing is very essential. The Punjab Government should be helped. The Akalis in Punjab have saved Punjab. Now the ISI agencies don't dare to come to Punjab. So, the Badal Government should be helped in all respects. Supposing, there is a war between India and Pakistan, Punjab has to fight that war. If the Punjab people are with us, only then we can win. So the entire country must help Punjab Government. Any party or any political party which wants to destablise Punjab Government must be discouraged. Nobody can win elections in Punjab except the Akalis. Though I am a Congressman, I am not an Akali, I am a practical person, not theoretical. I know that ground realities are as such in Punjab. So they should be helped by all means. Secondly, I would request that the farmers of Punjab and Haryana should be helped. They are contributing 70 per cent to the foodgrain pool of the country. Sir, Haryana should be given at least Rs. 1000 crores as aid because we have no water. There is no irrigation facility in Haryana, drinking water is not available, roads are in a very bad shape and it is the same with electricity. What to talk of all these, even in Delhi it is very bad. You are seeing it everywhere in the country. So, I would request that help must be given to Haryana if you want the country progress. I would request one thing to the Finance Minister. In future the Budget should be presented on the 28th of Februrary because for the last two years the Budget is always presented in the middle of the year. So I will pray to God that this Government lasts for that period also so that they can present the Budget on 28th of February. I pray for that.

9 PM

I am praying for you. I am not praying for anybody else.

Then, Sir, I want to make an appeal. I live in Chandigarh and Kalka. Now, Himachal is an industrially backward State. Kalka was in Nalagarh in H.P before the division of Punjab. But the topography of the area has not changed. It is not our fault that we have been put in Haryana. It is the fault of those leaders who did it. And Punjab also suffers. I request that Kalka, Pinjore Block, Panchkula District, Yamunanagar and Ambala should also be declared industrially backward. Why only Himachal areas? We will also contribute something to the country.

These areas should also be declared industrially backward. Sir, when an area is declared industrially backward, there is no income-tax for five to six years, there is no sales-tax and many other facilities are made available in that area. Sir, climatically it is a good area. We can develop these areas industrially. I request the Central Government to kindly accept this demand. I had made this submission last year also. Then there is another heart-burning issue. From Kalka to Parwanoo it is only a distance of one kilometre. These two towns are linked through STD. I mentioned it last time and I don't want to blame that Government. They have gone as an unhappy lot. The Minister has also gone. I don't know whether he had won or not. But he had promised that he would do it. The bureaucracy did not allow him to do it. Sir, from Kalka to Parwanoo it is a distance of only one kilometre and there is STD. From Parwanoo to Shimla, which

is a distance of 90 kms., it is a local call. Sir, the whole of Himachal is through local calls, thanks to Sukh Ram, who won on account of that. So, from Kalka to Parwanoo, it is STD. From Kalka to Chandigarh, which is a distance of 25 kms. and Panchkula, it is STD. The then Minister had promised that he would do it in no time. But as you know, Sir, so far as the bureaucracy is concerned, papers move at a very slow speed. When the bureaucrat start functioning, India will become America. There is no doubt about it. We are much better than those people. The only problem is that in our country the file doesn't move. They say there is no weight on it. It is not the paper-weight, Sir. And the paper here means the currency. It is the weight of the currency. Things don't move in our country. That is the tragedy. And we always blame the previous Governments! So far as this Government is concerned, it has been in office only for the last two months. We cannot blame this Government for the ills done by the previous Governments. But the responsibility has fallen on their shoulders now. They have to decide what they are going to do now. I do hope that Mr. George, who is a very competent man, can do it, if he wants to do things. If he doesn't want, then it is my bad luch. I can't help it. I do hope that he will help me in this regrd.

Mr. Vice-Chairman, Sir, how many more minutes are you going to give me? I hope you are not going to *bajaofy* the *ghanti* imediately.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I thought you did't need the *ghanti!* You will yourself regulate yourself. But I think you have made all your points.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, ...*(Interruptions)*...

SHRI LACHHMAN SINGH: Oh! you are speaking daily. You are speaking daily and spoling the whole show of the House. Sir, we behave with dignity in this House. But we feel shame when we go out. People say, "Why do you fight like small boys"? It is very shameful. I feel rather insulated that we fight like crows in the House. It is very insulting. We should not do that. Anyway, it is not in my hands. But, Sir, I have never done it. I think you have never seen me doing it. I never get up unnecessarily and cry. Well, the media persons also like that. They will talk to them only. They will never talk to me because they don't know me since I don't cry. They talk only to that man who cries, as if only he is a good person. They don't know that Lachhman Singh was in the Haryana Government for fifteen years. So, they will not talk to me. I won thrice as M.L.A. in Haryana. They will not talk to a person who knows everything. They will talk only to a person who cries here in this House and who creates *halla-gulla,* as if he is a good person. Anyway, I don't want to indulge in such matters.

On the whole, Sir, the present Fiance Minister has followed in the foot-steps of the previous Governments. If things go well, the production will definitely go up. And creation of jobs will also be created. Mr. Vice-Chairman, Sir, everybody wants a government job. Nobody wants to work in factories. They say, हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए, उसमें काम कुछ नहीं करना पड़ता और फिर पक्के होने के बाद हम खसम बन जाएंगे सरकार के और उसके बाद जिन्दाबाद-मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर देंगे।

So, evrybody wants Government job. Nobody wants to work in a factory or somewhere else. So, I request Shri George Saheb that he will do something for me about what I have said here at this late hour. At least, the Telecommunication Department will be called upon to do the needful. They can do it tomorrow. It is not a big job. It can be done tomorrow. I will go on praising you. I am here for another four years and I will go on praising you. Don't worry. There cannot be any whip for discussion

in the House. While I am ready to vote according to the whip, there is no whip on talking. So, I have a free will. So, do it today and let me know that you have done the job. I will be very happy on hearing that. Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to you for giving me an opportunity to speak on the Budget.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, there is no arrangement for dinner.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): There is arrangement for dinner.

श्री ओंकार सिंह लखावत: सर, डिनर का अरेंजमेंट नहीं है?

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Sir, let us adjorn the House. We can discuss it tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Yes, there is arrangement for dinner. You have exhibited such remarkable patience which was also praised by Sardar Lachhman Singh.

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बात कहने से पहले जो कुछ देख रहा हूं उसके बारे में केवल यह कहना चाहूंगा कि एक शहर में एक व्यक्ति बहुत जोरदार भाषण दे रहा था। वहां से कोई गुजरा तो उसने देखा कि केवल तीन आदमी, श्रोता, बैठे हैं पंडाल में और बहुत जोरदार भाषण हो रहा है और वे तीनों बड़े गौर से उसे सुन रहे हैं। उस व्यक्ति को यह देखकर बड़ी उत्सुकता हुई और उसने जाकर पूछा कि भाई, आप तीन आदमी किसलिए बैठे हो? वे कहने लगे कि हम सुनने वाले नहीं हैं, हम तो बोलने वाले हैं, इनके बाद हमारा बोलने का नम्बर है इसलिए बैठे हैं। हम तो बोलने के लिए बैठे हैं। तो यहां भी केवल बोलने वाले ही बैठे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री ओंकार सिंह लखावत (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं केवल सुनने के लिए बैठा हूं।

प्रो० राम बक्श सिंह वर्मा: मैं भी सुनने के लिए बैठा हूं।

श्री ओ० रामगोपाल (मध्य प्रदेश): मैं भी सुनने के लिए बैठा हूं।

श्री ओंकार सिंह लखावत: हम विशेष रूप से आपको सुनने के लिए बैठे हैं।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला: सर, वर्तमान जो बजट है इस बजट को आंकने के लिए पिछले दिनों जब बजट पेश हुआ, उसके बाद मैंने बहुत सी अखबारें पढ़ी कि कौन इसका स्वागत करता है और कौन इसका विरोध करता है, आडिटोरियल्स भी पढ़े और, उपसभाध्यक्ष जी, मैंने यह पाया कि बजट का स्वागत करने वालों में बहुत बड़े-बड़े धन्ना सेठ और पूंजीपति थे, चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के जो वक्ता हैं, वे थे और एन०आर०आई० के संगठन थे और अमीर लोगों ने या ऐसे लोगों ने जिनका देश की आम साधारण जनता से कोई लेना-देना नहीं है, उन्होंने इस बजट का स्वागत किया। तो, उपसभाध्यक्ष महोदय, जाहिर है कि यह बजट गरीब का बजट नहीं है, यह बजट इस देश के किसान का, मजदूर का बजट नहीं है। इसमें अचम्भा भी क्या है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सरकार से और आप उम्मीद भी क्या कर सकते थे? जैसा बजट उन्होंने बनाया है, यह उनकी नीतियों के बिल्कुल अनुकूल है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बजट पर बोलते हुए मैं किसान के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूं।

महोदय: माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के पैरा 6 में यह बात मानी है कि कृषि व्यवसाय के तौर पर नकारात्मक हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन 5 मिलियन टन कम हुआ है, इसे उन्होंने अपने बजट भाषण में स्वीकार किया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, 5 मिलियन टन गेहूं की कीमत और आस्ट्रेलिया से मंगाए गए गेहूं की कीमत का अगर हिसाब लगाया जाए तो उसका यह मतलब है कि देश के किसान को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इस फसल के कम होने से और यह जाहिर है कि पिछले 2 साल से किसान की 4 फसलें खराब हो चुकी हैं और किसान को पिछले 2 साल में बेमौसमी बरसात की वजह से और कीड़ा लगने की वजह से नुकसान हुआ है। मुझे इस बारे में केवल एक बात कहनी है कि वित्त मंत्री महोदय ने किसान के नुकसान की भरपाई करने के लिए एक फूटी कौड़ी का भी मुआवज़ा देने का प्रावधान नहीं रखा है। यह निहायत अफसोस की बात है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में देश के किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा है और इसके ऊपर सबकी निगाह टिकी है। सरकारी पार्टी के मंत्रियों ने भी और प्रधान मंत्री

जी ने भी यह बात स्वीकार की है कि किसान की हालत इतनी खराब है। मैं चाहता था कि वित्त मंत्री महोदय कम से कम आत्महत्या करने वाले गरीब किसान के आश्रितों के आंसू तो पोंछ देते। महोदय, इस देश में अगर हवाई-जहाज से गिरकर कोई आदमी मर जाए तो उसके आश्रितों को 10 लाख रुपया मिलता है और बिना मांगे मिलता है लेकिन किसान की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करें तो आप कम से कम 5 लाख रुपए तो उसके आश्रितों को दे दो। वरना वह एक आदमी की आत्महत्या नहीं होगी बल्कि पूरा परिवार उसके साथ मर जाएगा। ऐसी परिस्थिति में मैं उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्री इसके लिए बजट में कोई न कोई प्रावधान करेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अपने बजट भाषण के पैरा 7 में वित्त मंत्री महोदय ने यह माना है कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी है पर इस अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए आज की परिस्थिति में उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जरूरत इस बात की थी कि किसान के लिए काफी बड़ा पैकेज इस वर्तमान बजट में रखा जाता और खेती का नवीनीकरण किया जाता। जो फसलें किसान को पेट भरने लायक कमाई नहीं दे सकतीं, उसके बजाय दूसरी फसलें उगाई जा सकती थीं और क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज किया जा सकता था और अन्य बातें भी की जा सकती थीं लेकिन इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसी बजट के पैरा 7 में वित्त मंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करने की बात कही है और उसी के साथ उन्होंने यह बात भी कही है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें इन्फ्लेशनरी ट्रैड को रोकने के लिए इस बजट में उपाय किए गए हैं। आप मुझे माफ करिएगा, मेरा हिसाब जरा कमजोर है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बजट के आने के बाद एक डॉलर सवा बयालीस रुपए का हो गया है। रुपए की कीमत इतनी नीचे चली गई है। सब चीजें महंगी हो गई है जिसके कारण गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है, मुश्किल हो गया है। मैं यह बात बहुत भारी मन से कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक तरह से वित्तीय संस्थाओं ने चाहे वह वर्ल्ड बैंक हो या दूसरे देश हों, उन्होंने हमारा एक तरह से बॉयकाट कर दिया है। इससे निपटने के लिए उन्होंने कौन से प्रावधान किए हैं? मैं समझता हूं कि रुपए का अघोषित अवमूल्यन करके उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है।

वित्त मंत्री ने बजट में यह बात भी कही है कि कृषि की पैदावार के लिए जल का बड़ा महत्व है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बात को स्वीकार करने के साथ मैं यह बात कहना चाहूंगा कि क्यों नहीं वित्त मंत्री महोदय ने जल की वह सारी परियोजनाएं, ऐसे बड़े भारी प्रोजेक्ट जिन पर 5-5, 10-10 और 15-15 हजार करोड़ रुपया खर्च हो चुका है लेकिन किसी न किसी वजह से अंतर्राज्यीय झगड़ों में वह उलझी हुई है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा की एस०वाई०एल० नहर पंजाब में जिस पर 80-90 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है केवल 5, 7, 10 परसेंट ही काम बाकी है। हजारों करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो चुका है और इसी तरह से और भी जितने प्रांत हैं वहां भी अंतर्राज्यीय झगड़ों में कितने ही प्रोजेक्ट हैं जिनसे पानी किसानों के खेतों को लग सकता है परन्तु वह रुके पड़े हैं। परन्तु इस सरकार ने यह नहीं बताया है कि अंतर्राज्यीय झगड़ों का निबटारा करके क्या ऑलरेडी पड़े हुए प्रोजेक्ट का उपयोग करके इस देश के किसानों को पानी देने की कोई कोशिश सरकार करेगी? तो मैं आपको इसको साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें वित्त मंत्री जी ने जहां पर कृषि में रुपए को बढ़ाने की बहुत चर्चा की है, इस बात को कहा है, दूसरी ओर यूरिया के एक थैले पर 50 रुपए प्रति कीमत बढ़ा दी और इस पर 25 रुपया वापिस लेने के बाद भी फिर भी यूरिया का थैला महंगा है। इसके अलावा खेती में काम आने वाली चीजों पर भी उन्होंने सेस् लगा दिया है, एक्साईज ड्यूटी लगादी है। किसान को अगर एक हाथ से दो रुपए देने का प्रयत्न किया है तो दूसरे हाथ से किसान का बटुवा एक तरह से चुरा लिया गया है। आज इस देश में किसान बहुत परेशान है कि इस बजट में किसान के लिए कोई चीज नहीं है। यूरिया के दाम के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय और इस सरकार को इतनी चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने पहली बार सुना कि यूरिया का किलो में भाव होता है, मैंने यूरिया का भाव, खाद का भाव टनों में सुना था। यूरिया कोई सब्जी नहीं थी, यूरिया कोई सोना नहीं था जिसका भाव किलों में आंका जाए। इसमें भी क्या चालाकी की बात थी कि सरकार कहने में संकोच करती थी कि हमने यूरिया का भाव 50 रुपए कट्टा या इतने हजार टन हमने बढ़ा दिया है। तो मैं दरखास्त करूंगा और उम्मीद रखूंगा कि वित्त मंत्री महोदय, कृपा करके 25 रुपए कट्टे की बढ़त की बढ़त वापिस ले लीजिए। किसान की एक नया पैसा देने की भी क्षमता आज नहीं है। उसके साथ ही वित्त मंत्री महोदय ने नवार्ड को पांच सौ करोड़ रुपए में से सौ करोड़ रुपए दिए हैं और चार सौ करोड़ रुपए और बैंकों से दिलवाना चाहते हैं और यह भी कहा है कि किसानों को कर्जे में बड़ी राहत देने लगे हैं, उनको ब्याज में बड़ी

राहत देने लग हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो कॉस्मेटिक बातें हैं इनसे किसान का पेट भरने वाला नहीं है। सच बात यह है कि जो नरसिम्हन कमेटी बैंकों के सुधार के लिए थी, उसके सामने इण्डियन बैंक एसोसिएशन ने यह बात रखी कि इस देश में प्रायोरिटी सैक्टर को 40 प्रतिशत की जो आज पूंजी की रिजर्वेशन है उसको घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए। इससे बड़ा किसान और गरीब विरोधी क्या हो सकता है चूंकि प्रायोरिटी सैक्टर में खेती, ग्राम्य विकास और इस तरह से जो गरीब लोगों की योजना है वह इसमें शामिल है। वित्त मंत्री महोदय ने कोई चर्चा नहीं की है। वित्त मंत्री महोदय ने यह भी नहीं कहा कि वह किसान के लिए जो इतनी उंची ब्याज की दरें हैं वह न्यूनतम 6 प्रतिशत मुकर्रर करेंगे ताकि किसानों को राहत हो, इसकी भी चर्चा नहीं की गई है। वित्त मंत्री महोदय ने यह भी नहीं कहा कि जो बैंक कर्जे में किसानों की जमीन कुर्क करवाकर नीलाम करवा देते हैं और किसानों को घर से बेघर कर देते हैं इस किसान विरोधी कानून को वापिस ले लेंगे तथा किसानों को राहत देंगे, इसकी भी इसमें कोई चर्चा नहीं की गई है।

मैं नहीं समझ सकता कि किसान के लिए इस बजट के अंदर कौन सी बात उन्होंने रखी है? वित्त मंत्री महोदय ने पैरा-13 में तिलहनों के उत्पादन की बड़ी सराहना की है। मैं उनका स्वागत करता हूं कि किसी बात की तो सराहना उन्होंने की है। लेकिन उसका नतीजा क्या है? इस सरकार के बनने के चार हफ्ते के बाद वैजीटेबल घी की 200 रुपये प्रति टिन कीमत बढ़ गयी है। महोदय, यह पीठ थपथपाने की उसमें कौन सी बात थी कि गरीब आदमी के लिए एक टिन पर दो सौ रुपये बढ़ जाएं? ऐसा रिकार्ड तो आज तक किसी सरकार ने नहीं रखा है। तो देश में औसतन जो जोत है, जमीन की जो होल्डिंग है, वह 1/3 एकड़ रह गयी है। यह जो आंकड़े हैं, यह सरकार के आंकड़े हैं। कृषि मंत्रालय ने पिछले दिनों एक ऐडिशनल सैक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जिसके जिम्मे यह बात लगायी थी कि वह कमेटी पंजाब और हरियाणा में जाकर पता करे कि वहां पर किसानों पर सरकार के कर्जे की क्या स्थिति है। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें यह है कि पंजाब में 60 प्रतिशत किसान और हरियाणा में पचास प्रतिशत किसान कर्जे के बोझ के नीचे दबे हुए हैं और जो प्राइवेट सूदखोर हैं, उनसे पंजाब और हरियाणा के जो किसान कर्जा लेते हैं, वह 62 प्रतिशत इन प्राइवेट सूदखोरों से लेते हैं और केवल 38 प्रतिशत आपके बैंक किसान को एडवांस देते हैं। सर, प्राइवेट जो सूदखोर हैं वह 24 से 36 प्रतिशत ब्याज की दर लेते हैं। यह बात आज जग जाहिर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका पता न हो। महोदय, आजादी के बाद देश में जी०डी०पी० में जो खेती का कॉन्ट्रीब्यूशन था, खेती का जो हिस्सा था वह 60 प्रतिशत था वह आज घटकर 30 प्रतिशत रह गया है। इस देश की 75 प्रतिशत आबादी जो कृषि के ऊपर निर्भर थी वह आज केवल पांच प्रतिशत कम हुई है और देश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। इसका साफ मतलब यह है कि आज देश की टोटल जो वेल्थ है, टोटल जो देश जो देश के अंदर अर्थतंत्र है, इसमें से 70 प्रतिशत लोगों का तो 30 प्रतिशत हिस्सा है और 30 प्रतिशत लोगों का 70 प्रतिशत हिस्सा है। महोदय, 30 प्रतिशत का भी नहीं, केवल एक प्रतिशत लोगों का 70 प्रतिशत हिस्सा है, असली बात यह है क्योंकि शहरों में भी गरीब आदमी बहुत है। ऐसा नहीं है कि केवल गांवों में ही गरीबों की मानोपलि है। गांवों और शहरों में गरीबी और अमीरी की खाई आज और ज्यादा गहरी और चौड़ी हो गयी है। पिछले तीन साल में उत्तर भारत में 25 हजार किसान खुदखुशी कर चुके हैं जिसमें से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यू०पी० और दिल्ली के किसान शामिल हैं। मैं इस सदन में बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं। मैंने कोशिश की है और मैं मांग करता हूं कि अगर इन आंकड़ों के बारे में किसी को शक है तो सदन के सदस्यों की एक कमेटी, जिसमें सारी पार्टियों के सदस्य हों, बनाकर इसका ब्यौरा लिया जाए। मैंने सरकार के इदारों से दरख्वास्त की। मैंने ऐग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के वाइस चांसलर को यह बात कही कि आप सैंपल सर्वे करवा लो। आप अपने विद्यार्थियों की एक टीम बनाओ जिसमें एक-एक प्रोफेसर उसका हैड हो सकता है। यह जो बात है, इसको कितने दिन दबाया जाएगा? कोई उठता है और कहता है कि पांच सो किसान मरे हैं, कोई उठता है और कहता है कि 300 किसान मरे हैं। महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में एक लाख से ज्यादा किसान पिछले तीन साल में खुदकुशी कर चुके हैं और केवल उत्तरी भारत में पच्चीस हजार से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं। ऐसे किसानों की मैंने—जब मैं कंडोलैंस के लिए अपने इलाके में जाता हूं—सौ लोगों की अभी पिछले तीन महीने की इसी साल की लिस्ट मेरे पास मौजूद है। एक-एक गांव में पचास-पचास लोग मरे हैं। जो सदस्य जानना चाहे, मैं इस बात को साबित कर सकता हूं। तो महोदय, बहुत बुरी हालत आज किसानों की है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यह जो डिज़ास्टरस पोजीशन है, इससे देश को बचाने के लिए किसान को ग्राहत देनी पड़ेगी। किसान को अन्न चाहिए...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अब आप समाप्त कीजिए।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट से जयदा नहीं लूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि किसान को अन्न चाहिए, बम नहीं चाहिए। हम उम्मीद करते थे कि जो आटोमिक एनर्जी है इसका पीसफुल परपज के लिए उपयोग होगा। आज किसान की आटोमिक एनर्जी के द्वारा मदद की जा सकती है। किसान की जो फसल है, जो सब्जी है, जो फल हैं उनकी सेल्फ लाइफ इसके द्वारा बढ़ सकती है। आपके जो बीज हैं जिनमें कीड़ा लगता है, आटोमिक एनर्जी के द्वारा रेज क्रास करके उसमें कीड़ा लगने से रोका जा सकता है। आपकी फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी। आप इसका हजारों तरह से उपयोग कर सकते हैं, टैस्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, वैदर कंडीशन का पता करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इन सारे परपज के बजाय आपने किसान को रोटी देने के बजाए, उसे बम दे दिया। अरे, बम तो उसके पेट में ही रखा था, वह आत्म हत्या कर रहा है वह बम ही तो है भूख का। इसलिए मैं इस सरकार से यह उम्मीद रखता हूं कि कृपया करके किसान की बात को सुनिए। मैं इस सरकार के ऊपर यह इल्जाम लगाता हूं कि यह किसान विरोधी सरकार है, यह गरीब विरोधी सरकार है। आस्ट्रेलिया से आयात किए गए गेहूं के घोटाले का जिसका लोक सभा में यह ऐलान किया गया है कि उसकी आप सीबीआई से इन्क्वारी करायेंगे, इसमें मुझे अभी भी संदेह है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि इसके पीछे बहुत बड़े-बड़े शक्तिशाली लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं। एसटीसी के चेयरमैन का नौकरशाही में बड़ा मशहूर स्थान है। उनके खिलाफ अभी भी चार सीबीआई की इन्क्वारी पेंडिंग हैं लेकिन वह इतने मजबूत हैं कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। वह उस वक्त भी चेयरमैन थे और आज भी चेयरमैन हैं। मैं इस हाउस के माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि सीबीआई की इन्क्वायरी की बात कहने से काम नहीं चलेगा। आप सीबीआई से इन्क्वायरी करवाओ, इनके खिलाफ मुकदमें दर्ज करवाओ, इनको गिरफ्तार करो, इनकी जायदाद कुर्क करो और अगर इनके खिलाफ इल्जाम साबित हो जाए तो इनकी जायदादों को नीलाम करके देश का घाटा पूरा करो। फरवरी, मार्च के महीने में किसान की फसल जब खलिहान से मंडी में आने वाली थी तब 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं किसलिए मंगवाया गया जबकि इस देश में एक बोरी गेहूं की भी जरूरत नहीं थी? आप एफसीआई की रिपोर्ट देखिए, उनके लीगल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखिए, उनके डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट देखिए, यह इतना बड़ा घोटाला है। मैं सरकार पर और मंत्री महोदय पर उपसभाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इल्जाम लगाता हूं। इन्होंने दो महीने का समय दिया उन गलत आदमियों को सारे डाकूमेंट्स में अल्टर करने के लिए। मुझको इस बात का पता है कि एसटीसी के चेयरमैन ने बहुत से डाकूमेंट्स बदले हैं और बहुत से ऐवीडेंस में टैम्पर किया है और इस सरकार ने जानकर उनको मौका दिया। पहली अप्रैल को प्रधान मंत्री जी की मौजूदगी में मैंने यह इल्जाम लगाया था लेकिन उन्होंने बात टालकर कुछ भी नहीं किया। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं।

"लीडरों ने गाया गीत राम राज्य का,
क्या हुआ किसान कामगार राज्य का।"

राम राज्य की बात ठीक कही, यह मुझको पता नहीं है लेकिन किसान और कामगार के राज्य की बात करके जो आप महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। मैं चार बातें कह कर खत्म करता हूं। मैं मांग करता हूं कि किसान को दिए जाने वाले, मजदूर को दिए जाने वाले खेती के लिए दिए जाने वाले पैसे की ब्याज की दर को घटाकर छह प्रतिशत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। किसान की कर्जे की वसूली में जमीन की नीलामी को तुरन्त बन्द करना चाहिए। पिछली चार फसलों का मुआवजा किसान को दो और गेहूं का किसान को रेम्यूनरेटिव प्राइसिज मिलना चाहिए। आत्म हत्या करने वालों के आश्रितों को पांच लाख रुपये की राशि दी जानी चाहिए। बेरोजगार नौजवानों को पांच सौ रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। कीड़े मार दवाइयों में मिलावट करने वालों को, नकली दवाइयां बेचने वालों को 10 साल की सजा होनी चाहिए और फसल बीमा योजना तुरन्त लागू की जानी चाहिए।

और अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि खेती का माईनाइजेशन, क्रोपिंग पैटर्न में तब्दीली करके नये बीज, नई फसल, कर्ज की सहूलियत, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग का इन्तजाम करके ऐसे सेन्टर मुकर्र करने चाहिए जो किसान एक किला फसल में कम से कम 50 हजार रुपये की पैदावार बढ़ाये, तभी आप किसान का और देश का भला कर सकते हैं। इसमें 25 करोड़ रुपये का पैकेज का नत में मैं एक बात कहता हूं....

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): सुरजेवाला जी खाना भी तैयार है।

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला : मैं एक शेर के साथ अपनी बत समाप्त करता हूं और किसान के मन की पीड़ा इस शेर के द्वारा दर्शाना चाहता हूं:—

"जिस खेत से धहकान को न रोजी मयस्सर, उस खेत के हर गूंसां-ए-गन्दम को जला दो।" आज यह हालत है इस देश के अन्दर। मैं वार्निंग देता हूं सरकार को समझ लेना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI K. RAHAM KHAN (Karnataka) : Mr. Vice-Chirman, Sir, after a long wait you have provided me an opportunity to present my views on the Budget. The Budget for 1998-99 presented to the Parlaiment by the hon. Finance Minister is before us for discussion. The people, the Press, experts, industries and the common man, have reacted to this Budget differently. But everybody is unanimous that this Budget is directionless and has no message and is not inspiring.

Mr. Vice-Chairman, Sir, the hon. Finance Minister, in his long Budget Speech has stated the good objectives of his budget. On page 2 of his Budget Speech he has enumerated the good objectives which this Budget is going to achieve. I am afraid, he is in a dreamland. He will not be able to achieve any of the good objectives. This Budget will not strengthen the foundation of the Indian economy, as he dreams. It will not boost the rural economy. There is nothing in the Budget which will boost the rural economy. It will not restore the momentum of industrial growth and revive the capital market, as he dreams. We have seen how the capital market is reacting. Sometimes some hon. Members had said that we should not care for the capital market.

It is the hon. Finance Minister's dream that he will revive the capital market, but, I am afraid the results are before us. It will not help him to create job opportunities. It will also not reduce his dependence on borrowed capital. Borrowed capital means that borrowings will increase in this Budget. This is evident. It is not a Budget where there is transparency to understand it. So many things are happening in this Budget, which is a mystery. They are trying to project and place it, but unfortunately, it is not possible.

Inflation cannot be contained. That is the unanimous view in the country. Domestic savings will not increase because there is no incentive for savings. He has ultimately said that it will reduce the bureaucratic hurdles. I am afraid, in this Budget there will be more bureaucratic hurdles than what he wants to remove.

My other friends, and the Leader of the Opposition, Dr. Manmohan Singh, had said, "The figures he has presented are a gimmick." As everybody has said, I repeat it, the Finance Minister, in his anxiety to present a glorious picture, a bright picture, has sometimes used words such as budget—revised, revised estimates and sometimes budget estimates. Wherever it is convenient, he has changed it. It is not correct. There should be consistency. In accounting we say there should be a consistent policy

Wherever it is convenient he has used "Revised Budget; wherever convenient, "Budget Estimate", and then compare it. He has misled. the people—with all responsibility I use the word-misled the whole nation. I would like to dwell upon only a few things because of lack of time. On education, the hon. Finance Minister in his Budget Speech has said, "Education is the key vehicle or social transformation."

'Universalisation of elementary education and eradication of illiteracy are the central elements of our social policy. Government also plans to implement the Constitutional provision for making primary education free and compulsory up to fifth standard'. The Finance

Minister says that to achieve this objective, the Budget provides nearly fifty per cent increase in the total budgetary allocation.

Mr. Vice-Chairman, Sir, this is a statement which has nothing to do with reality. There is absolutely no allocation for primary education. In fact, he has killed primary education. The allocation for primary education is absolutely nil. There is no increase in the allocation for primary education.

What does even this fifty per cent increase which is being talked of amounts to? As has been pointed out here, about Rs. 1,000 crores is meant for salaries. Another Rs. 1,000 crores is for higher education. There is an increase in the allocation by Rs. 300 crores in respect of the University Grants Commission. I am not saying that it should not be increased. But what about the priority which you have mentioned that you are going to give to primary education, removal of illiteracy, women's education, girls' education?

If you go into the details—I am not spelling out all the details—you find that there is absolutely no budgetary allocation for these things.

For example, elementary education. the amount allocated in the Budget Estimates for 1997-98 was Rs. 304 crores. As per the Revised Estimates, the figure is Rs. 301 crores. For this year, i.e. 1998-99, the amount allocated is Rs. 304 crores! What is the great thing you have done? What is the Constitutional right you are going to give? Why do you say one thing in your Budget speech and do the Contrary in actual practice?

There are many other things like this. For example, the nutrition programme, the mid-day meal programme. You have not increased the allocation. The figures, as per the Budget Estimates for last year and the Budget Estimates for this year, are Rs. 651 crores and Rs. 667 crores, respectively. What you have done is to compare the allocation for this year with the Revised Estimates for last year. As the whole money was not spent, the Revised Estimates figure is Rs. 560 crores. You should compare the allocation for this year with that made for last year, in the Budget Estimates. When you make this proper comparison, you find that the allocation has gone up from Rs. 651 crores to just Rs. 667 crores. Is this an increase? This just makes up for the inflation. Allocation for this programme is a primary requisite. Everybody is agrred that the mid-day meal programme is an important component in education. That is how you can attract students to schools. But it has been given a go-by.

Then, we have what is called 'Other Programmes'. This is what we would like to know about. Earlier, for 'Other Programme', the amount allocated was just Rs. 6 crores. You have now allocated Rs. 106 crores for 'Other Progrmmes'. What for is this huge allocation? Where would this amount go? Generally, the allocation has been of the order of Rs. 5 crores, Rs. 3 crores, Rs. 2 crores, etc. Why a sum of Rs. 106 crores has been allocated for 'Other Programmes' is not revealed. One does not know. It is for the Finance Minister to explain.

Then, adult education. You have reduced the allocation. Then, distance education. It is very important. You would not be able to eradicate illiteracy through formal education. It is not possible. Formal education is very cost-effective. There is no allocation for distance education, mass education. What about the national open school scheme?. By this you can help drop-outs. Thousands of drop-outs can be educated through the national open school system. But there is absolutely no allocation.

Therefore, Sir, what is this Budget? If you make a micro-analysis, what do you find? You are only deceiving the people. You are saying one thing, but doing another thing. That is why we always question. That is why we say, you have a hidden agenda.

You have provided Rs. 37 crores for modern Indian languages. Sir, I am not against Sanskrit. You have to promote it. For Sanskrit, Rs. 37 crores. For all modern Indian languages, Rs. 37 crores. I think there should be a proportionate increase in the allocation for promotion of other languages also. The allocation for the last year was only Rs. 6 crores. Then, for the All India Institute of Technical Education, you have not increased the allocation. For the IITs you have increased the allocation. So, your thrust is confusing. You are a confused Government. That is why I say that it is a directionless Budget which will not inspire anybody. It may inspire a party, no doubt about it. As a party, you have to praise the Budget, no doubt about it. But, I am not criticising it for the sake of criticism.

Mr. Vice-Chairman, Sir, there is absolutely no correlation between what the Finance Minister has said and the allocation on education. There is no time for me. I can go on illustrating that in every sector you have tried to hide more and reveal less, with the result that you are looked with suspicion. We look at you with suspicion because you are not giving to Parliament what you are supposed to give. So, kindly correct it. Don't do this. It is not good, and it is not in the interest of Parliament.

Then, you have talked so much about welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and minorities. You blamed the Congress Government of appeasing minorities. You said, "Look, we are going to give them a programme. We are going to give them an economic programme. We are going to give them an educational programme. We will not appease them, but we will understand them." This is also your empty slogan. What is it that you have done practically? Let us come to the practical terms. You have done nothing. You have said in your manifesto, and you have told the public, "The real issues of the minorities are social backwardness, economic backwardness and educational backwardness." How have you tackled these? As a member of a minority, I would have appreciated it. I would have congratulated you if you had come with some programme. But you have no programme. You are worse than a slogan-shouter. When somebody does it, you call it appeasing. You do not do it. You say, "No. We will be equal." No minority asked you to give charity. You understand the social, economic and educational backwardness. Have you done it? Have you provided for it in your very first Budget? You say that it is your maiden Budget. You have not provided for it.

In his Budget Speech, the Finance Minister took credit for having given Rs. 41 crores for the Minorities Development Corporation. Mr. Vice-Chairman, this allocation of Rs. 41 crores is not a fresh allocation. In the Budget Estimates for 1997-98, Rs. 41 crores was provided for. That was the share capital that the Government of India had to give to the Minorities Development Corporation In 1997-98. They had not released that amount. So, in 1998-99 they have released that amount. What is this? Is this not an appeasement? Why should the share capital which was already due and which should have been given, find a place in the Budget Speech of the Finance Minister? You are saying that you are giving Rs. 41 crores for the Minorities Development Corporation. You are telling the world, "Look, we are giving Rs. 41 crores." Had you given another Rs. 40 crores to the Maulana Azad Foundation which would have helped education of minorities, I would have appreciated it. You have given nothing. You have not given a paisa for the educational upliftment of minorities.

Mr. Vice-Chairman, I have one or two points more, and I will end.

You have levied service charges. Again you are discriminating here. At one place, the hon. Finance Minister says, "I want to remove the Inspector *raj.*" Yes, you have given certain things to the

small-scale industry. But, now, what are you doing to the same Excise Department? You have given it more opportunities to perpetuate the Inspector *raj*. You have introduced the service tax on the services of architects, interior decorators, management and different other sorts of services of professionals. But, who will monitor it? The same very inspectors, whom you are taking out from one place and putting on this monitoring job.

Here too I would like to point out a grave lapse that you have committed. You have included the services of the chartered accountants, but not of the advocates. Advocates also take fees. They also represent. In the Supreme Court they take lakhs of rupees as fees. This is also a service profession. As chartered accountants do tax practice, so do advocates and sales-tax practitioners. But you have included only the service of the chartered accountants leaving out the services of the other two, as if you are discriminating against some professionals and in favour of the others. So, you have to look into this aspect also.

Sir, PNR/GIR number is to be put for so many things, including while opening a Savings Bank Account. Even a *coolie* wants to open an account. If you say put a PNR/GIR number, the bank would not open his account. Don't you want that small savers should open a bank account? This proves that it is a thoughtless Budget. Sir, they just want to present the Budget and want us to pass it. It is strange that nobody in the bureaucracy has pointed out this farce. Sir, Parliament is an institution. When they present the Budget, they have to take our criticism in a spirit to correct their shortcomings.

Sir, I welcome the abolition of the Urban Land Ceiling Act, but while doing so he should have come with some details. On the housing side, the Minister says they are going to give support by way of 100 per cent exemption to the World Bank aided projects. Sir, how many World Bank aided projects are there. They have to be very practical. The World Bank aided projects will be taken by certain big builders. Small contractors will not be able to take the World Bank aided projects. That shows you are giving tax exemptions to big contractors and builders and not to small ones.

Sir, if you look into the Finance Bill and the Budget and the Statement of the hon. Finance Minister, you will find a number of contradictions. I have been participating in the Budget debates for the last four years. There is so much contradiction in the figures contained in the hon. Finance Minister's speech, the Budget and the Finance Bill.

Sir, the Finance Minister is not here. Anyhow, the Minister of State for Finance is here. I hope he has been taking note of the points that have been raised. I hope, while replying to the debate, hon. Finance Minister will reply to the points in a proper manner. I would like to have a categorical answer on education, GIR/PNR numbers while opening a new bank account and on the reasons of his excluding certain professions from the service tax.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Dr. B. B. Dutta.

DR. B. B. DUTTA (Nominated): If any other Member is left, you can call him.

THE VICE-CHAIRMAN (SH. TRILOKI NATH CHATURVEDI): I think with your cooperation it has been possible to accommodate each and everybody.

DR. B. B. DUTTA: Sir, the House had heard Dr. Arun Kumar Sarma, Member of parliament from Asom Gana Parishad party of Assam. If the House is perceptive enough then, have definitely got some messages from him Though he talked on the Budget, strictly speaking he strayed away from the Budget, only to make some general but deep observations. I think he has given a

message that reflects the anguish the political leaders and people in the North-East suffer from.

Sir, you will kindly notice that in this House, so far no tribal Member has participated in this Budget.

THE VICE-CHAIRMAN (SH. TRILOKI NATH CHATURVEDI): I was waiting for Mr. Angou Singh. When I called his name, he was not there. That is why I did not announce.

DR. B.B. DUTTA (Nominated): Sir, there is a problem. Our tribal friends sometimes find it very difficult to get along with the process with which I can. I have waited, but they have left, on their patience had been exhausted. Here is an alienation that comes in the way you conduct the House, the way the respective parties conduct themselves. I am just drawing your attention. They feel alienated. They should be encouraged. They are insiders. If they speak out their mind, then, we will get something out of that. That is the only intention. But anyway, Sir, I will be very brief because there are only few to listen.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): We are all here to listen to your points.

DR. B.B. DUTTA: I will just confine myself to a few ponts pertaining to the North-East which Dr. Arun Kumar Sarma did not spell out, but hinted.

In paragraph 51 of the Finance Minister's speech he has given another message to the North-East that he is coming out with a non-lapsable Central Resource Pool that each Ministry must spend 10 per cent of its total allocation in the North-East. If it does not then the difference between what is spent and what is not spent within 10 per cent will come to the Central Resource Pool and it will be there for the North-East and it will not lapse. Sir, once we get this message, naturally, common people will be very much delighted. But I for one have got great misgivings because two former United Front Government Prime Ministers, Shri Deve Gowda and Shri I.K. Gujral visited the North-East. Shri Deve Gowda stayed there for 7 days. He created history. by announcing that Rs. 6,100 crores would be given to the Norht-East over and above the Plan allocation. Then, Mr. Gujral stayed there for two or three days. He reiterated the same stand and further added something. Now, make an assessment, what has happened out of this
Rs. 6,100 crores. I told him in this House that it was a bluff. The Prime Ministers were misled by the bureaucrats. I checked up with the Planning Commission. They were equally ignorant. I met the then Industry Minister, Mr. Murasoli
Maran. He said that they were trying to find out the projects to spend that money. So, they were in the process of finding out projects and getting them sanctions and things like that and two or three sanctions were made available. So, this was the fate of that big deal. Now, on the heel of that comes this non-lapsable Central Resource Pool. Sir, the Government accouants are maintained on a cash basis. The amount which is not spent lapses. It cannot be carried over. So, I understand what can be done only is this that sanctions can be revalidated. But sanctions have to be revalidated with reference to schemes. My question to the hon. Finance Minister is this: What are the schemes? He is ominously silent about the schemes. I am inclined to speculate. The Shukla Commission visited North-East. It gave a report. A lot of discussion took place about marvellous aspects of this report which, to my mind, is not yet that marvellous. It dealt with only part of the problems. Then there was a Working Group in the Planning Commission.

They had worked out something. Is the hon. Finance Minister referring to those things? The hon. Minister has not spoken about the Shukla Commission. He has not spoken about the Prime Minister's package. I would like to know as to what the Non-Lapsable Resource Pool is

about? We would like to know as to what exactly this is. So far as the people of the North-East, particularly, the tribal people, are concerned, if you promise something to them, and if later on, nothing happens, you alienate them more. You create more distrust. So, I request the hon, Minister that what the earlier Governments have done, for God's sake, don't do it. At least, stand on the honest wicket and tell them as to what is what.

Secondly, the hon. Finance Minister has again come out with something relating to the North-Eastern Development Finance Corporation. When the North-Eastern Development Finance Corporation was first created, it became a non-starter. It charged interest at the rate of 22 per cent. So, there were no takers. Very recently, the interest rate has been lowered. But the North-Eastern Development Finance Corporation has not taken any management banking functions which is very important from the point of view of the requirements of the North-East. Side by side, you find that the IDBI is there. Then the SIDBI is there. You will find that their functions are contracting. Now, I would like to know as to what the Finance Minister has in mind. Will he allow the IDBI and the SIDBI to contract their functions? What you are trying to give through the North-Eastern Development Finance Corporation, is being taken back through the contraction of the activities of other vital institutions. If you see the ground reality, you will realise that it is not the North-Eastern Development/Finance Corporation which is very important for the development of the North-Eastern region. But it is the SIDBI, it is the IDBI, which are much more important to the North-Eastern region than the North-Eastern Development Finance Corporation. So, I would request the Finance Minister to pay heed to this aspect.

Sir, the Finance Minister also has come out with a statement that the North-Eastern Council is being restructured, and a Bill will come to complete the process. We welcome it. We have already welcomed it. For years, we have been demanding that the North Eastern Council should be restructured. Mr. Pranab Mukherjee knows this. He had attended some of the meetins of the North-Eastern leaders. He had been in touch with us. He had been advising us. We wanted that the North-Eastern Council should be restructured. So, that is a welcome step. But the main question is that the Finance Minister has not said anything about the funding policy of the North-Eastern Council. How do you propose to give funds to the North-Eastern Council? The current funding policy is such that it does not mean much. Suppose, there was no North-Eastern Council, then the Central Government would have spent some money in the Central sector, various Departments would have spent some money on some projects, If the North-Eastern Council is merely there to take up these projects and complete them, what is the necessity of the North Eastern Council? Sir, you will recall that the North-Eastern Council was conceived with great imagination. These small States which have been created, and the region as a whole, with all its structural rigidities, with its alienation from the mainland, even physically, by being just attached to the Siliguri neck, have got a number of regional problems. There is the problem of marketing, there is the problem of development of infrastructure and so on. So, what the North-Eastern Council was supposed to do was that the States would look after themselves. But the North-Eastern Council will draw up projects which will address the needs of the region as a whole. It is exactly this function that the North-Eastern Council is not doing.

It is not doing because it is not being funded in that fashion. It is not doing because the North-Eastern Council is not being asked to prepare any integrated regional plan to develop its communication system and integrate it

with the rest of the country, and to draw up plan for highways. We demanded double lane railways, double lane roadways. We wanted elevation of certain sector of the roads which are always flooded by mid Himalayan rains, cutting off North East from the rest of India. These are the things. The entire North-East should be brought closer. The North-Eastern States—Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh—should be brought closer so that the home market is expanded, the regional market is expanded and the regional market gets more and more integrated with the rest of the country—the National market. This is not being done. Then what is the use of having the North-Eastern Council? So, I invite his attention to the purpose of restructuring the Council. If you are restructuring the North-Eastern Council, then what for are you restructuring it? For God's sake, kindly try to fulfil the very objective, the very purpose for which it was set up. Give it adequate funds so that it can draw up such plans that within the North-East itself the markets expand and it gets adequately connected with the national markets for to-and-fro movement of goods and people. Sir, this is one thing.

My fourth submission is this. Dr. Arun Sarma has mentioned that the Governments of the North East is not able to pay salaries to their employees. It is a fact. In the North-Eastern States, a big financial crisis is going on. The origin of this financial crisis can be traced way back to 1989.Mr. Mukherjee—the hon. Member is sitting here; he knows it very well; he had been the Deputy Chairman of the Planning Commission; he had been the Finance Minister—knows thoroughly what the problem is. Sir, the non-Plan gap before 1989 was first met, and then the Central Plan assistance was added to it. Now, the Central Plan assistance determines the size of the State Plan! Now what is happening here? We find that the Central Plan assistance, more or iess, remains constant. This year also, the assistance is Rs. 29,538 crores. In 1997-98, it was Rs. 27,001 crores. So, the increase is not much. If you allow for inflation adjustments, it is neutralised. If you calculate the hike in the cost of capital goods, then it is more than neutralised. If you calculate the fall in the value of the rupee, then it is much more neutralised, but if you consider the situation in the North-East, then it is further neutralised, and you will find that actually, the Central Plan assistance is declining in real terms. Now with the Central Plan assistance, declining and their non-Plan gap always increasing, the crises is deepening. The Rangarajan Committee which was set up to fix this problem gave them a temporary relief that up to 30 per cent they can divert the Plan funds to meet their non-Plan expenditure, i.e., from their own Central Plan assistance, up to 30 per cent they can divert. Now, some of the States are crossing that limit also. You see a problem has occurred which is not being solved. Now it is this problem which has to be solved. I do understand that the North-Eastern States and quite a number of other States also do not have the reputation of managing their finances well. But by saying that they have not managed their finances well, you cannot allow in the North-East, which is stricken by insurgency, which is slipping out of your hands, a terrible situation to emerge which will not be manageable after a time. The process of alienation continues. Now in the finanical situation also, this kind of unimaginative handling is there; you are not attending to this problem. What is required is, you set up a new expert Committee to find out ways and means to being the financial affairs in the North-Eastern States under control. The States should also be asked to have more financial discipline. There are a number of reasons why the financial discipline is breaking down in the North-Eastern States.

Those things should be attended to. But the flow of finance should not be choked. You have created States which

are not fully economically viable. Everybody knew that they were created out of expendiency. Chief Minister after Chief Minister have been telling us in the meetings that these States were created out of expediency and not on the considerations of economic viability or any other factor. You have to look after the States for a number of years.

How do you look after? In what way are you handling the States? So, a major responsiblity comes to the Centre. These four things should be taken care of. I would like to mention specifically about the North-East because things are becoming worse and worse every day.

Sir, just one or two points and I am finished. One of the hon. Members from the ruling benches said that there was emphasis on the rural sector, on the agricultural sector. Okay. I would just like to draw the attention of the Finance Minister to the coir industry. There is a coir industry in the southern States, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and all the coastal areas. Now they produce rubberised coir. There are Rs. 80 crores worth of industries. They are in a quite healthy form. In this Budget, for the first time, you have put 5% excise duty on this. I am telling you that this is going to hit them very badly. These industries are environment-friendly. These industries employ a large number of women. The end product is biodegradable. Now they will be finished, because of this 5% excise duty, by the synthetic foam industry which is not environment-friendly and which is non-biodegradable will thrive. These are small mistakes which are being committed. But they have a much larger effect on the society.

Now I would like to draw the attention of the Finance Minister to another thing. This is the last point. We have got Rs. 2,000 crores worth of power cable industry. For the last two years or so this industry is also facing a problem. Our addition to power generation is very less. We have been able to achieve less than 50%. As a result of that the damand for cables is very low. There are low-level purchases by major core sector customers resulting in a negative growth rate of 15% to 20%. So, this industry is also reeling under pressure. Now what is the problem that they are facing? In this case, while domestic cable producers will be saddled with additional non-modvatable special customs duty of 8%, effective 11% on imported raw materials, imported cables by power generation projects will be exempted from this additional special customs duty. It means that you can import finished products. But when you are producing inside the country you are at a disadvantage. Just to demonstrate the point I will give you the calculations. In the case of imported cables for power generation projects, the basic customs duty is 20% special customs duty is 2%, special CVD nil. The total comes to 22%. In the case of idigenous cables, the basic customs duty is 20% and the special customs duty is 2% on imported raw materials. On top of this, the excise duty on finished cables is 18% and the Central sales-tax on finished cables is 4%. The total comes to 44%. So, the duty structure is 44% and 22%. How do the indigenous producers survive? In paragraph 121 of the Finance Minister's Budget Speech, if I am correct, he has given an assurance that if some anomalies are found, they will be corrected. So, I would like him to make that correction. In the case of power transmission projects, on imported cables the basic customs duty is 20%, the special customs duty is 2% the CVD is 10% and the special additional duty is 8% effective 11%. The total comes to 43%.

Then for indigenous cables the basic duty is 20% per cent, special duty is 2 per cent, CVD is 10 per cent and 8 per cent special additional duty effective 11 per cent, is 11 per cent. The excise duty on finished cables is 18 per cent and Central Sales Tax on finished cables is 4 per cent. The total comes to 65 per cent. So it is 65 per cent versus 43 per cent. It menas we are favouring imports. Sir, it

requires correction. There is no improvement The situation remains the same in the case of petroleum refineries. Nothing has been done about it. There were some anomalies in the last Budget also. The same anomalies are there in this Budget. I would request the hon. Finance Minister to correct these anomalies; otherwise they will hit us very badly. Employment, income generation and everything will get affected. This is the least we can expect from the Finance Minister. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Now the discussion on the Budget is over. The hon. Finance Minister would reply to the debate at 12 o'clock tomorrow. I adjourn the House till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at eleven minutes past ten of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 11th June, 1998.